अपराजिता : वर्ष 53 अंक 01: 2025
स्थापना वर्ष : 1972 (प्रिंट), 2025 (ऑनलाइन)

नेपाल में अस्थिरता और युवा क्रांति

डॉ कृष्ण कुमार यादव
पूर्व शोध छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग

नेपाल केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं बल्कि *हिमालय की गोद में बसा मानव सभ्यता का जीवंत प्रतीक* है। यहाँ की धरती को *विश्व का छत* कहा जाता है जहाँ से निकलने वाली नदियाँ जीवनदायिनी बनकर बहती हैं। भौगोलिक दृष्टि से नेपाल दक्षिण एशिया का वह सेतु है जो भारत और चीन जैसी महाशक्तियों को जोड़ता है। ऐतिहासिक रूप से यह भूमि भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है और साथ ही गोरखा वीरता का प्रतीक भी, जिसने अपनी तलवार से एकता और साहस की अमिट छाप छोड़ी। सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल विविधताओं का अद्भुत संगम है—जहाँ हिन्दू और बौद्ध परंपराएँ एक-दूसरे में घुल-मिलकर जीवन का अनूठा दर्शन प्रस्तुत करती हैं। पशुपतिनाथ से लेकर लुम्बिनी तक, यह देश *आध्यात्मिक ऊर्जा और सांस्कृतिक गौरव* का अद्भुत स्रोत है। यहाँ की घाटियाँ केवल प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण नहीं हैं, बल्कि वे यह सिखाती हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य भौतिक समृद्धि ही नहीं, बल्कि *आत्मिक शांति और उच्चतर चेतना* की ओर भी यात्रा करना है। नेपाल की पहचान इसी संगम में है—*भौगोलिक विराटता, ऐतिहासिक वीरता, सांस्कृतिक विविधता और आध्यात्मिक गहराई*।

इसी नेपाल में 4 सितंबर 2025 से 12 सितम्बर 2025 के बीच की घटनाएँ मननशील मानस को घोर चिंता में डाल गयीं। 4 सितंबर 2025 को सरकार ने स्थानीय स्तर पर पंजीकरण न होने और गलत सूचना व अभद्र भाषा की चिंताओं का हवाला देते हुए 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बंद करने का आदेश दिया। फेसबुक और एक्स सहित कई प्लेटफॉर्म को ब्लॉक कर दिया गया। 8 सितम्बर को "जेन-जेड विरोध प्रदर्शन" के बैनर तले, हज़ारों लोग, जिनमें से ज़्यादातर छात्र थे, सड़कों पर उतर आए और प्रतिबंध और व्यापक भ्रष्टाचार दोनों की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने संसद पर धावा बोलने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस को पानी की बौछारें, आंसू गैस, रबर की गोलियां और अंततः गोलियां चलानी पड़ीं। शाम गृह मंत्री रमेश लेखक ने कार्रवाई के दौरान हुई मौतों की नैतिक ज़िम्मेदारी लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया। देर रात एक आपातकालीन कैबिनेट बैठक के बाद सरकार ने सोशल मीडिया पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया। प्रतिबन्ध हटाने के फैसले के बावजूद 9 सितंबर 2025 विरोध प्रदर्शन उग्र हो गए प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री ओली, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल और कई मंत्रियों के निजी आवासों में आग लगा दी, संसद भवन और सर्वोच्च न्यायालय की बिल्डिंग भी आग के हवाले कर दी गयी, सानेपा स्थित नेपाली कांग्रेस मुख्यालय और ललितपुर स्थित सीपीएन-यूएमएल कार्यालय सहित पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई। सेना तैनात कर दी गई और त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। प्रधानमंत्री ओली ने शाम 6 बजे एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें शांति बनाए रखने की अपील की गई और स्थिति को "अप्रिय" बताते हुए युवाओं और सरकार की "सोच के बीच अंतर" को जिम्मेदार ठहराया गया। कुछ ही घंटे बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। सेना ने मोर्चा संभाला किन्तु संसद भवन और सर्वोच्च न्यायलय की बिल्डिंग बचाने का कोई यत्न नहीं किया । एक दिन बाद ही परिस्थिति पर सेना नियंत्रण स्थापित कर पाई, फिर अनेक अनौपचारिक चर्चाओं के उपरांत 12 सितम्बर को रात दस बजे देश के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व प्रथम महिला न्यायाधीश सुशीला

किर्की को अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गयी।

यह महज 'सहज सत्ता परिवर्तन की घटना' नहीं। यह था भ्रष्टाचार, वंशवाद और नेताओं की ऐश्वर्यपूर्ण जीवनशैली से क्षुब्ध युवा विशेषकर जनरेशन-Z के अपनी सत्ता के प्रति घोर असंतोष की अभिव्यक्ति, लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रतीक संस्थाओं के प्रति नकार का भाव, सोशल मीडिया की अदृश्य और समानांतर सत्ता का उदघोष, महाशक्तियों द्वारा लोकतान्त्रिक अस्थिरता के हथियार का अप्रत्यक्ष प्रयोग, वर्तमान से असंतुष्ट पीढ़ी का सुखद भविष्य की प्रत्याशा में अतीत का गौरवपूर्ण बोध...और भी बहुत कुछ ।

भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म का कॉकटेल

राजशाही के खात्मे के बाद से ही राजनीतिक रूप से नेपाल में सत्ता तीन प्रमुख दलों —नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ नेपाल (सीपीआई-यूएमएल) और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ नेपाल (माओईस्ट सेंटर) के बीच हस्तांतरित होती रही है। 2020 के दशक के बाद में उभरती नई पार्टियाँ और स्थानीय चेहरों — जैसे कि कुछ नागरिक-आधारित समूह और मेयर स्तर के लोकप्रिय नेताओं ने परम्परागत संरचना को चुनौती देने का प्रयास जरुर किया है किन्तु ये भी वित्तीय शुचिता और पारदर्शिता के प्रश्न पर कटघरे में आते रहे और अंततः सत्ता-निर्माण की इस प्रक्रिया उन्हीं तीन प्रमुख दलों के बीच हस्तांतरित होती रही जो 'नेपोटिज्म' और 'क्लाइंटेलिज्म' के नेटवर्क का खुले आरोपों से घिरी हुई हैं।

नेपाल में भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म की समस्या केवल सतही नहीं बल्कि गहराई तक पैठ चुकी है। छोटे स्थानीय निकायों से लेकर बड़े राष्ट्रीय स्तर के ठेकों और नीतिगत फैसलों तक इसकी परछाई स्पष्ट दिखाई देती है। हाल ही में उजागर हुए कई मामलों ने यह साबित कर दिया है कि किस तरह सत्ता, अफसरशाही और व्यावसायिक हितों का त्रिकोण बनकर सार्वजनिक संसाधनों की लूट कर रहा है। उदाहरण के लिए, नेपाल टेलीकम्यूनिकेशन अथॉरिटी में "टेरामॉक्स प्रोक्योरमेंट स्कैम" ने पूरे देश को झकझोर दिया। इसमें पूर्व मंत्री मोहन बहादुर बस्नेत, पूर्व चेयरमैन दिगंबर झा, पुरुषोत्तम खनाल सहित 16 व्यक्तियों और दो कंपनियों को आरोपी बनाया गया। इसी तरह राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र में हाई-कम्प्यूट उपकरणों की खरीदी में लगभग 160 मिलियन रुपये की गड़बड़ी पाई गई, जहाँ टेंडर प्रक्रिया को ठेकेदार के पक्ष में मोड़कर घटिया उपकरण खरीदे गए। नेपाल टेलिकॉम के बिलिंग सिस्टम कांट्रैक्ट में बिना प्रतिस्पर्धा के चीनी कंपनी को ठेका दिया गया और 330 मिलियन रुपये से अधिक की गड़बड़ी हुई। एयरलाइन्स सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा। कुख्यात "वाइड-बॉडी स्कैम" में नेपाल एयरलाइन्स कॉर्पोरेशन के तत्कालीन जीएम सुगत रत्न कंसाकार सहित कई अधिकारियों को दोषी पाया गया और उन्हें जेल और जुर्माने की सजा हुई। भूमि लेन-देन में भी राजनीतिक संरक्षण के तहत बड़े घोटाले हुए हैं। महेंद्रज्योति, साङ्गा, कवरेपालांचोक ज़िले में भूमिघोटाले में पूर्व प्रधानमंत्री माधव कुमार नेपाल और 92 अन्य को आरोपी बनाया गया। भ्रष्टाचार केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं है। स्थानीय सरकारें भी इसमें बराबर की भागीदार रही हैं। स्याङ्जा ज़िले के अर्जुनचौपारी ग्रामीण नगरपालिका के तत्कालीन चेयरपर्सन दिर्ग नारायण अर्याल और 12 अन्य पर आरोप है कि उन्होंने ढलान निर्माण जैसी परियोजनाओं में घटिया काम कराकर लाखों रुपये हड़प लिए।

भ्रष्टाचार की इन सभी घटनाओं में एक समान पैटर्न है—राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अधिकारी और उनके परिजनों या नज़दीकी सहयोगियों को न केवल ऊँचे पद और ठेके मिलते हैं बल्कि सार्वजनिक संसाधनों की लूट को भी "सामान्य" बना दिया जाता है। नेपोटिज्म की यह संस्कृति नियुक्तियों में भी दिखाई देती है, जहाँ पारिवारिक संबंध और राजनीतिक निष्ठा योग्यता और पारदर्शिता पर भारी पड़ते हैं।

Gen-Z: सुलगता बारूद जिसे जली राख समझा गया

पिछले कुछ वर्षों में बेरोज़गारी, महंगाई और अवसरों की कमी ने युवा जनसंख्या में असंतोष पैदा किया। जिस देश की युवा आबादी का बड़ा हिस्सा विविध देशों में सड़कों के किनारे ठेलों और खोमचों पर 'मोमोस' और 'चाऊमीन' की दूकाने लगाने के लिए विवश हो, जिस देश की नव यौवनाएं अनेक देशों में 'वेश्यावृत्ति के लिए अभिशप्त हों' उसी देश में नेताओं के परिवारों के लड़के लड़कियों का शाही जीवन, और सार्वजनिक मंचों पर उनका प्रदर्शन आम जनमानस के मन में व्यवस्था के प्रति घृणा उत्पन्न करता ही है। इसी घृणा ने सोशल मीडिया की सहायता से पारंपरिक दलों पर आरोपों को तेज़ी से फैलाया: भ्रष्टाचार, जमीनों और संसाधनों का दुरुपयोग, नियुक्तियों में पारिवारिक प्राथमिकता — यह सारी बातें जनता के बीच गहरे असंतोष को उभारती रहीं। अमेरिका-आधारित टेक कंपनियों के प्लेटफ़ॉर्म नेपाल में युवाओं की आवाज़ का सबसे बड़ा औज़ार बन गए। भ्रष्टाचार और वंशवाद से उपजी निराशा को इन्हीं प्लेटफ़ॉर्म्स ने विस्तार दिया और सड़कों पर आक्रोश में बदल दिया।

नेपाल के इस पूरे आन्दोलन को Gen-Z का आन्दोलन कहा गया । वह पीढ़ी जिसे पिछले आंदोलनों की निराशाओं और टूटे हुए सपनों ने निस्संग बना दिया है। अवसर और उपयुक्त परिस्थितियों के अभाव में जिसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ही अपना जीवन मान लिया है। सत्ता और व्यवस्था के लोगों की नजर में जिनकी कीमत "जली राख" से अधिक नहीं थी। वह पीढ़ी "सुलगता बारूद" की मानिंद प्रतीत हुई, उसने यह दिखाया कि आज का युवा केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। जैसे ही अन्याय, वंशवाद, या भ्रष्टाचार की कोई एक घटना "माचिस की तीली" बनती है, यह पूरी ऊर्जा *भयावह दावानल* में बदल सकती है।

वास्तव में Gen-Z के इस आन्दोलन ने दिखाया कि *यह खतरा भी है और संभावना भी*। खतरा इसलिए कि इस तरह की उग्र ऊर्जा बेकाबू होकर अराजकता और अस्थिरता को जन्म देती है। बिना संगठित ढाँचे और दीर्घकालिक योजना के आंदोलन अचानक भड़ककर अचानक ठंडा भी पड़ जाता है। दूसरी ओर संभावना इसलिए कि यही पीढ़ी सत्ता को पारदर्शिता, जवाबदेही और नई नेतृत्व-शैलियों के लिए मजबूर कर सकती है। Gen-Z किसी भी देश की राजनीति को निर्णायक रूप से बदलने की क्षमता रखती है। यह नेपाल के लिए ही नहीं अपितु सभी सरकारों के लिए यह चेतावनी है कि यदि उन्होंने इस पीढ़ी की आकांक्षाओं को गंभीरता से नहीं लिया, तो "सुलगता बारूद" कभी भी विस्फोट कर सकता है।

सोशल मीडिया की समानांतर सत्ता

नेपाल के इस पूरे घटनाक्रम ने सोशल मीडिया की समानांतर सत्ता की अनुभूति करायी है, यह चिंतनीय है कि नेपाल ऐसे सोशल साइट्स को जिनका स्वामित्व राज्य से बाहर है उनके नियमन हेतु राज्य में पंजीकरण का कानून लाता है, ये प्लेटफोर्म राज्य द्वारा रजिस्ट्रेशन के प्रावधान को स्वीकार नहीं करते और प्रतिबन्ध लगाने की स्थिति में उस राज्य की जनता इन प्लेटफॉर्म्स का बहिस्कार करने की जगह अपने राज्य प्रतीकों और सरकार के प्रति ही हिंसक विद्रोह कर देती है । लोग इसे जीवन-शैली और नागरिक अधिकारों पर आक्रमण मानते हैं। परिणामस्वरूप विरोध तेज़ी से बड़े पैमाने पर फैल जाता है और परंपरागत विरोध की सारी सीमायें टूट जाती हैं। नेपाल के इस प्रकरण ने यह साबित किया है कि सोशल मीडिया केवल "एक तकनीकी उपकरण" नहीं है—यह एक सूचना-परिवेश है जिसे वैश्विक शक्तियाँ, कॉर्पोरेट नीतियाँ, और स्थानीय राजनीतिक लक्ष्य सभी प्रभावित करते हैं। इसलिए इसे केवल घरेलू मुद्दे के रूप में न देख कर, एक अंतरराष्ट्रीय रणनीतिक संसाधन के रूप में भी परखा जाना चाहिए।

क्षेत्रीय संदर्भ: एक पैटर्न तो है

दक्षिण एशिया के पिछले कुछ सालों पर नजर डालें तो नेपाल की वर्तमान स्थिति यह केवल एक देश की आंतरिक हलचल नहीं, बल्कि एक बड़े पैटर्न का हिस्सा प्रतीत होती है। श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के भ्रष्टाचार और चीन के कर्ज़-जाल ने जनता को सड़कों पर ला खड़ा किया। म्यांमार में सेना और लोकतंत्र समर्थकों की जंग अब भी जारी है और वहाँ अमेरिका, चीन और आसियान की खींचतान साफ़ दिखाई देती है। बांग्लादेश में शेख हसीना की सत्ता-विरोधी लहर और हालिया राजनीतिक संकट भी इस पैटर्न की ओर इशारा करता है। नेपाल अब इस क्रम का चौथा उदाहरण बना है। सवाल उठता है कि क्या यह सब महज़ संयोग है या दक्षिण एशिया को किसी प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ लोकतांत्रिक अस्थिरता को प्रोत्साहित करके महाशक्तियाँ अपने-अपने हित साध रही हैं।

नेपाल की राजनीति को केवल घरेलू असंतोष और भ्रष्टाचार–वंशवाद के चश्मे से देखना पर्याप्त नहीं होगा। वहाँ की अस्थिरता और हालिया जनांदोलन की पृष्ठभूमि में वैश्विक और क्षेत्रीय महाशक्तियों की सक्रिय भूमिका भी उतनी ही निर्णायक है। नेपाल भौगोलिक दृष्टि से एक ऐसा रणनीतिक चौराहा है, जहाँ उत्तर में चीन, दक्षिण में भारत और विश्व राजनीति में अमेरिका की दख़लंदाज़ी एक-दूसरे से टकराती है। यही कारण है कि हर बार जब काठमांडू में सत्तांतरण होता है या जनता सड़कों पर उतरती है, तो उसका असर केवल नेपाल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि बीजिंग, दिल्ली और वॉशिंगटन के गलियारों तक गूंजता है।

नेपाल दक्षिण एशिया में एक स्ट्रैटेजिक बफर ज़ोन है, जहाँ अमेरिका लंबे समय से लोकतंत्र और मानवाधिकार के नाम पर सिविल सोसाइटी, एनजीओ और मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से अपनी पैठ बनाता आया है। Gen-Z का विद्रोह जिस डिजिटल स्पेस से फूटा, उसका बड़ा हिस्सा पश्चिमी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आधारित था। पश्चिमी देशों के लिए यह आंदोलन इसलिए उपयोगी रहा कि वे इसे लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की लड़ाई की तरह प्रस्तुत कर सकते हैं और नेपाल में चीन-निकट राजनीतिक धड़ों पर दबाव बना सकते हैं।

दूसरी ओर, चीन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। नेपाल में चीन ने पिछले एक दशक में 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ गहरे रिश्ते बनाए हैं। के पी शर्मा ओली जैसे नेताओं को चीन का समर्थक माना जाता है। हालिया विद्रोह ने चीन-समर्थक धड़ों की साख कमजोर की और चीन चिंतित है कि कहीं यह अस्थिरता उसकी आर्थिक सुरक्षा योजनाओं को प्रभावित न कर दे।

इसलिए कहा जा सकता है कि यह आंदोलन पूरी तरह "स्वत: स्फूर्त" नहीं था। पश्चिम के लिए यह अवसर था कि नेपाल को भारत और चीन दोनों के लिए अस्थिर मोर्चा बना दिया जाए। चीन के लिए यह चुनौती थी कि वह अपनी मित्र सरकारों की रक्षा करे और राजनीतिक स्थिरता बहाल करे। भारत के लिए यह चिंता का विषय है क्योंकि नेपाल की अस्थिरता सीधे उसकी सुरक्षा, सीमाई इलाकों और क्षेत्रीय संतुलन पर असर डालती है।

इस प्रकार, नेपाल का यह संकट केवल घरेलू असंतोष का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक बड़े भू-राजनीतिक शतरंज का हिस्सा है, जहाँ युवा आंदोलन, सोशल मीडिया और राजनीतिक अस्थिरता को बाहरी शक्तियाँ भी अपने हितों के अनुसार आकार देने की कोशिश कर रही हैं।

निहितार्थ

- नेपाल का वर्तमान संकट केवल सरकार बदलने या भ्रष्टाचार-विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरा प्रश्न उठाता है कि क्या मौजूदा लोकतांत्रिक संस्थाएँ जनता की अपेक्षाओं को पूरा कर पा रही

हैं? चुनाव होना निस्संदेह लोकतंत्र का अहम आधार है, लेकिन केवल चुनावों से लोकतंत्र जीवित नहीं रहता। उसका असली मापदंड यह होना चाहिए कि जनता को न्याय, अवसर और जवाबदेही उपलब्ध हो। नेपाल के संदर्भ में यह और भी स्पष्ट है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मीडिया की निष्पक्षता और जवाबदेही के तंत्र यदि मज़बूत न हों, तो जनता धीरे-धीरे लोकतांत्रिक प्रक्रिया से निराश होकर वैकल्पिक — और कभी-कभी खतरनाक — रास्तों की ओर बढ़ती है।

- सामान्यतः चुनाव से सत्ता परिवर्तन लोकतंत्र का वैध और शांतिपूर्ण आधार माना जाता है, परंतु नेपाल में यह परंपरा टूटती दिखाई दे रही है। लोग सड़कों पर उतरकर हिंसा और संघर्ष के बल पर सत्ता को चुनौती देने लगे हैं। यह सवाल उठने लगा है कि क्या नेपाल का लोकतंत्र धीरे-धीरे "लोकतंत्र" से "भीड़तंत्र" में बदल रहा है? यदि जनता का विश्वास संस्थाओं से उठ गया और भीड़ ही अंतिम निर्णयकर्ता बन गई, तो फिर संविधान, संसद और न्यायपालिका की प्रासंगिकता क्या रह जाएगी?
- अरस्तू की दृष्टि से यह स्थिति लोकतंत्र के *भीड़तंत्र* में पतित होने की ओर संकेत करती है। भीड़ जब न्यायपालिका, संसद और संवैधानिक संस्थाओं को जलाकर अपनी शक्ति दिखाने लगती है तो लोकतंत्र के बुनियादी आधार—*संवाद, संस्थागत मजबूती और विधि का शासन*—कमजोर पड़ जाते हैं। यह भीड़-तंत्र कभी भी किसी ठोस समाधान की ओर नहीं ले जाता, बल्कि सत्ता के अनवरत और अस्थिर चक्र को जन्म देता है।
- इसी पृष्ठभूमि में नेपाल में एक नई बहस उभर रही है — क्या नेपाल फिर से हिंदू राजशाही की ओर देखना शुरू कर चुका है? गौरतलब है कि नेपाल दुनिया का एकमात्र हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, जहाँ 2008 तक राजशाही बनी रही। जब राजशाही को समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई, तो जनता ने इसे नई शुरुआत माना था। लेकिन पिछले डेढ़ दशक में लगातार सरकारों का अस्थिर होना, नेताओं का वंशवाद, भ्रष्टाचार और अंतरराष्ट्रीय शक्तियों की दख़लंदाज़ी ने जनता को निराश कर दिया है। आज जब लोकतंत्र अपने वादे पूरे करने में असफल हो रहा है, तो कुछ वर्ग खुलेआम यह कहने लगे हैं कि "कम-से-कम राजशाही के समय स्थिरता तो थी।"हाल के प्रदर्शनों में यह स्वर स्पष्ट रूप से सुनाई दिया कि यदि लोकतंत्र सिर्फ सत्ता का खेल बनकर रह गया है, तो जनता हिंदू पहचान और राजशाही को विकल्प के रूप में देख सकती है।
- यही कारण है कि नेपाल में हो रहे परिवर्तन केवल सत्ता-परिवर्तन भर नहीं हैं बल्कि एक *संवैधानिक और वैचारिक संकट* का प्रतीक हैं। क्या नेपाल हिंदू राजशाही या किसी अन्य व्यवस्था की ओर लौटना चाहता है, यह एक अनुत्तरित प्रश्न है, किंतु यह निश्चित है कि मौजूदा लोकतंत्र ने अपनी वैधता और स्थिरता को खोना शुरू कर दिया है। अरस्तू के सिद्धांत के आलोक में कहा जा सकता है कि जब तक शासन समाजहित की ओर केंद्रित नहीं होगा, तब तक यह पतन और पुनः-पतन का चक्र चलता रहेगा।
- स्पष्ट है कि नेपाल का संकट केवल उसके आंतरिक विरोधाभासों का परिणाम नहीं है। यह उन वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों की अदृश्य लड़ाई से भी संचालित होता है, जो हिमालय की इस छोटी-सी धरती पर अपनी-अपनी छाप छोड़ना चाहती हैं। भारत के लिए यह "पड़ोसी सुरक्षा" का प्रश्न है, चीन के लिए "रणनीतिक विस्तार" का

अवसर और अमेरिका के लिए "इंडो-पैसिफिक कंटेनमेंट" का हिस्सा। दुर्भाग्य यह है कि इस खींचतान में नेपाल की जनता अपने ही लोकतंत्र को सुधारने के बजाय बाहरी महाशक्तियों की बिसात पर मोहरा बनती जा रही है।

अंततः, नेपाल की त्रासदी और संभावनाएँ दोनों ही उसके भौगोलिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक चरित्र से जुड़ी हैं। यह भूमि जहाँ हिमालय की चोटी पर आध्यात्मिकता बसती है, वहीं घाटियों में विविधताओं का संगम जीवन की नई राह दिखाता है। आज जब नेपाल का लोकतंत्र गहन संकट से गुजर रहा है, तब यही प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण हो उठता है—क्या नेपाल इस संकट से एक नए, अधिक उत्तरदायी और जनोन्मुखी लोकतंत्र के रूप में उभरेगा या फिर किसी वैकल्पिक सत्ता संरचना, यहाँ तक कि राजशाही की ओर लौटेगा? यह उत्तर नेपाल की जनता और उसके युवाओं के हाथ में है, जो आज जली राख भी हैं और सुलगता बारूद भी।

* * *